सहायता करने की योजना पर आप कोई विचार कर रहे हैं? क्या ऐसे कोई दृष्टिकोण है?

SHRI T.R. BAALU: Sir, the programmes are not suffering for want of funds. This particular State, namely, Uttaranchal, will be sending us a proposal and we will definitely be assisting them.

SHRIMATI S.G. INDIRA: Sir, I would like to know from the hon. Minister whether this programme is likely to be extended to other parts of the country, particularly Tamil Nadu.

SHRI T.R. BAALU: Sir, Tamil Nadu is one of the developed States. I do not think it is necessary as such to have this programme there.

SHRI SANTOSH BAGRODIA:This campaign is good. But the Ministry needs more teeth. Therefore, will the hon. Minister like to think of bringing in some law so that this programme is implemented effectively, and the culprits are dealt with severely? I would also like to know whether the Ministry is going to take some action against those States which are not taking this issue of environment seriously, because this is going to be a serious problem.

SHRI T.R. BAALU: I do agree that NEAC does not have enough teeth at present. But my intention is not to bite any State. The States have to behave properly. That is my intention.

राजस्थान और उड़ीसा में केन्द्रीय विश्वविद्यालय

*446. **श्री जनेश्वर मिश्रः** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश में इस समय राज्यवार कितने केन्द्रीय विश्वविद्यालय हैः,

(ख) किस विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने के निर्धारित मानदंड क्या हैः,

(ग) क्या यह सच है कि राजस्थान और उड़ीसा जैसे राज्यों में कोई केन्द्रीय विश्वविद्यालय नहीं हैः, और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (डा.मुरली मनोहर जोशी)ः (क) से (घ) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) से (घ) इस समय देश में 18 केन्द्रीय विश्वविद्यालय है:, जिनका राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा इस प्रकार है:-

आन्ध्र प्रदेश	दो
असम	दो
दिल्ली	चार
महाराष्ट्र	एक
मणिपुर	एक
मेघालय	एक
मिजोरम	ए क
नागालैंड	एक
पांडिचेरी	एक
उत्तर प्रदेश	तीन
पश्चिम बंगाल	एक

केन्द्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना भारत सरकार द्वारा संसद के अधिनियम द्वारा की जाती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 (1992 में यथा संशोधित) में भी और अधिक केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने की अपेक्षा मौजूदा संस्थाओं में उपलब्ध सुविधाओं के समेकन और समन्वय पर बल दिया गया है। इस प्रकार राजस्थान और उड़ीसा में कोई केन्द्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव नहीं है।

Central Universities in Rajasthan and Orissa

†*446. SHRI JANESHWAR MISHRA: Will the Minister of HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT be pleased to state:

(a) the present number of Central Universities in the country, State-wise;

(b) the norms prescribed for granting Central University status to a university;

†Original notice of the question was received in Hindi.

(c) whether it is a fact that there is no Central University in States, like Rajasthan and Orissa; and

(d) if so, the reasons for the same?

THE MINISTER OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT (DR. MURLI MANOHAR JOSHI): (a) to (d) A Statement is laid on the Table of the Sabha.

Statement

(a) to (d) There are, presently, 18 Central Universities in the country as per the State/Union Territory-wise break up given below:

Andhra Pradesh	two
Assam	two
Delhi	four
Maharashtra	one
Manipur	one
Meghalaya	one
Mizoram	one
Nagaland	one
Pondicherry	one
Uttar Pradesh	three
West Bengal	one

A Central University is established by the Govt, of India through an Act of Parliament. The National Policy on Education, 1986 (as modified in 1992) lays emphasis on consolidation and expansion of facilities in the existing institutions rather than setting up of more Central Universities. As such, no new Central University is proposed to be set up in the States of Rajasthan and Orissa.

श्री जनेश्वर मिश्रः सभापति महोदय, हमने अपने सवाल में चार बिंदु रखे हैं जिसमें दूसरा बिंदु है कि किसी विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा देने के निर्धारित मानदंड क्या हैं?

इस सवाल का जवाब इस उत्तर में नहीं है, कृपया इनसे दिलवाइए।

दूसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, वह यह है कि मंत्री जी ने एक लिस्ट दी है। शिक्षा राज्य और केन्द्र दोनों का विषय है सभापति महोदय। आम तौर पर केन्द्रीय विश्वविद्यालय इसलिए रखे जाते हैं कि राज्य के विश्वविद्यालय उसको आदर्श मानकर अपना काम चलाएंगे। इसमें देश के कई राज्य हैं। राजस्थान, उड़ीसा के बारे में तो हमने पूछ लिया है और माननीय रंगनाथ मिश्र जी ने भी पूछा है। कई राज्य हैं, यहां तक मंत्री जी के बगल में नीतीश जी बैठे हैं, उनका राज्य बिहार भी है, मोती लाल जी का मध्य प्रदेश भी है। ये कई राज्य अछूते हैं, इन राज्यों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों हुआ, कब से हुआ और कब तक चलेगा। मंत्री जी ने एक हवाला दिया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति, जिसकी अभी इन्होंने चर्चा भी की थी, 1986 और 1992 में संशोधित हुई थी। उसमें सख्ती से कह दिया है कि नया केन्द्रीय विश्वविद्यालय न खोलकर, जो विश्वविद्यालय चल रहे हैं उन्हीं को सुचारू रूप से चलाया जाए। यह जवाब में है। हमको याद है जब डा. मुरली मनोहर जोशी इधर बैठते थे, हमारे मित्र .टी.एन.चतुर्वेदी जो अब राज्यपाल हो गए हैं, इधर बैठते थे, हमारा ख्याल है कि 1986 और 1992 के बाद,इधर से ये लोग मांग करते थे के इलाहाबाद विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय.....

श्री सभापतिः यह तो एक आदत है कि इधर बैठने वाले माननीय सदस्य उधर बैठते हैं तो प्रश्न पूछने और विचार करने में काफी अंतर हो जाता । ....(व्यवधान)... आप सीधा पूछ लीजिए। आप एक प्रश्न पूछ लीजिए कि आपने इधर बैठकर जो मांग की है, उसको पूरी कर रहे है या नहीं कर रहे हैं।

श्री जनेश्वर मिश्रः हां वही कहने जा रहा हूं कि आपने इधर बैठकर जो मांग की थी, अब आप शिक्षा मंत्री हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में परिवर्तन करके क्या उस मांग को पूरा करेंगे?

डा. मुरली मनोहर जोशी: श्रीमान, पहली बात तो यह है कि सरकार की भी यह नीति है कि देश में कुछ ऐसे विश्वविद्यालय जिनका स्तर अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हो, वे प्रत्येक राज्य में छांटे जाएं, विभिन्न राज्यों में छांटे जाएं और उनको अधिक मदद दी जाए। सम्माननीय सदस्य का जो आशय है कि प्रत्येक राज्य में कुछ ऐसे विश्वविद्यालय होने चाहिएं कि जो आदर्श रूप में काम करें, उनकी सहायता से और उनको देखकर अन्य विश्वविद्यालय अपना विकास करें। ऐसे विश्वविद्यालयों की छटनी का काम शुरू हुआ है। पहले पांच विश्वविद्यालय छांट लिए गए थे और इसके साथ-साथ इस बार दस-बारह विश्वविद्यालय, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग छांट रहा है। इसके अतिरिक्त देशभर में सौ से अधिक विद्यालयों को छांटा जाएगा जिसके आधार पर महाविद्यालय भी अपना विकास कर सकें। जो इनका आशय यह है कि प्रत्येक राज्य में कुछ ऐसी संस्थाएं होनी चाहिएं जो आदर्श हों, मानक हों, उसकी तरफ सरकार और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ध्यान दे रहा है। इन्होंने जो

दूसरा प्रश्न किया है, इसके बारे में मुझे यह निवेदन करना है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय के मामले की छानबीन हमने की है और यह देखा है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय को नया केन्द्रीय विद्यालय बनाने का प्रश्न नहीं है क्योंकि वह पहले केन्द्रीय विश्वविद्यालय था। उसके केवल रेस्टोरेशन का सवाल है, उसको फिर से केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाने का सवाल है। इसकी समीक्षा करने के लिए हमने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और अपने ब्यूरो को हिदायत दी है कि वह इस बारे में अपनी टिप्पणियां जल्दी से जल्दी देश करे।

श्री जनेश्वर मिश्र: सभापति महोदय, विश्वविद्यालयों में और खासतौर से केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में भी अध्यापकों के स्तर पर और विद्यार्थियों के स्तर पर जिस तरह की अनुशासनहीनता बढ़ी है, जो पढ़ाई होती है, उसके बारे में मैं जानता हूं और मंत्री जी भी जानते होंगे।

श्री सभापतिः फिर भी आप विश्वविद्यालय खुलवा रहे हैं।

श्री जनेश्वर मिश्र: मैं उस पर आ रहा हूं। ....(व्यवधान)...वह देश का चरित्र है इसलिए इस पर आ रहा हूं। दिल्ली में तो हम लोग रोज ही अखबार में पढ़ते हैं, सच तो यह है कि जिस विश्वविद्यालय में मेरा नाम था, मैं फीस देता था लेकिन दस दिन क्लास में जाता था। सच यह भी है कि मंत्री जी उस विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थे, एक साल में क्लास लेने जाते थे और तनख्वाह अलग लेते थे। ...(व्यवधान)...

डा. मुरली मनोहर जोशीः यह बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल भ्रामक बात है, विश्वविद्यालय में इसका पूरा परीक्षण हुआ। विश्वविद्यालय में, मेरे विभाग में मेरी कक्षाएं सब अध्यापकों से अधिक रही है। जब मैं छुट्टी पर भी रहा हूं तब भी मैंने कक्षाएं ली हैं। मैं बता रहा हूं कि यह बिल्कुल गलत बात है, राजनीति से प्रेरित है। ...व्यवधान)...

श्री सभापति: मेरी समझ में यह नहीं आता ...(व्यवधान)...

श्री बालकवि बैरागीः मेरे ख्याल से ये दस दिन विश्वविद्यालय जाते थे इसी से विश्वविद्यालय की दुर्गति हुई है। ....(व्यवधान)...

श्री सभापतिः मैं इसलिए पूछ रहा हूं आपने विश्वविद्यालय के संबंध में अपनी उपस्थिति, योग्यता का परिचय दे दिया, लेकिन इस प्रकार के विद्यार्थी कैसे निकले? ...(व्यवधान)...

डा. मुरली मनोहर जोशीः मुझे अफसोस है कि ऐसे विद्यार्थियों को कुछ लोगों ने राज्य सभा में भी भेज दिया।

श्री जनेश्वर मिश्रः सभापति जी, । मेरी बात पूरी नहीं हुई है।

श्री अमर सिंहः जैसा गुरु वैसा चेला।

श्री जनेश्वर मिश्र: सभापति जी, मेरी बात पूरी नहीं हुई है। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में और सारे विश्वविद्यालयों में कई ऐसे अध्यापक हैं जो छह-छह महीने क्लास में नहीं जाते ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः इसे छोड़िए, आज सीधे प्रश्न कर लीजिए।

श्री जनेश्वर मिश्र: सभापति जी, मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस बारे में राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कोई सिफारिश की है कि उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।

डा. मुरली मनोहर जोशीः सभापति जी, विश्वविद्यालय स्वायत्तशासी संस्थाएं हैं। ये अपने यहां अध्यापन, छुट्टियां और पढ़ाने के नियम स्वत्ः निर्धारित करती हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने ऐसी सिफारिश की हैं कि वहां पढ़ाइर्-लिखाई के क्या मानदण्ड होने चाहिए। अधिकांश अध्यापक इन मानदंडों को मान रहे हैं लेकिन कुछ विश्वविद्यालय, जैसे दिल्ली विश्वविद्यालय है, उन मानदंडों को मानने में अभी अपने आपको असमर्थ पाता है। हमारा यह प्रयास है पढ़ाई-लिखाई के घण्टे और जितना भी कार्य निष्पादित करना है, उसके मानदंड य. द्वारा निर्धारित हों और विश्वविद्यालयों की संस्थाऐं, उनकी एग्ज्यूकेटिव कौंसिल्स और परिषदें उन मानदंडों को अपने यहां स्वीकार करें और लागू करें लेकिन हम सरकार की ओर से विश्वविद्यालयों के प्रबंधन में अनावश्यक हस्तक्षेप नहीं करते और उसे उचित भी नहीं मानते।

SHRI BIRABHADRA SINGH: Sir, I would like to know from the hon. Minister whether the Poorvanchal University of Baripada, which is existing in the border districts of West Bengal, Jharkhand and Orissa, meets the criteria, by which it can be converted into a Central university.

डा. मुरली मनोहर जोशी: सभापति जी, इसका उत्तर मैंने पहले ही दिया है कि इस बारे में हम विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की सिफारिशों की प्रतीक्षा करते हैं। वे जहां-जहां जिन संस्थाओं को उचित मानकर छाटेंगे, उनकी मदद करेंगे और क्रमशः चरणबद्ध रूप से ऐसे विश्वविद्यालयों की गिनती बढ़ाएंगे जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त हों। उनका अनुसंधान उचित हो और जैसे-जैसे उन विश्वविद्यालयों की रिपोर्ट्स आती जाएंगी, उनका विकास करेंगे। एक्रिडिटेशन कमेटी सब जगह जा रही हैं। विश्वविद्यालयों का स्तरीकरण कर रही हैं कि कौन किस स्तर के हैं। उनके आधार पर उनकी सहायता और उनके विकास की योजना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के पास हैं।

डा. अबरार अहमदः सभापति जी, मूल प्रश्नकर्त्ता के इस प्रशन का "ख" भाग अभी तक अनुत्तरित है। माननीय सदस्य ने पूछा है कि केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाने के इसमें क्या मानदंड हैं, वे तो माननीय मंत्री बताएं साथ ही जो सूची केन्द्रीय विश्वविद्यालयों की दी गई है उसमें राजस्थान के बारे में स्प्ष्ट रूप से पूछ गया है। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि अन्य राज्यों में जो केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं, उनकी तुलना में राजस्थान विश्वविद्यालय का महत्व किसी भी

दृष्टिकोण से कम नहीं है। दो दशक से अधिक समय से रूटा (राजस्थान टीचर्स एसोसिएशन) की राजस्थान विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाने की मांग है लेकिन उसकी बराबर उनेक्षा हो रही है। मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि क्या उस पर कोई विचार किया जा रहा है? यदि किया जा रहा है तो कब तक राजस्थान विश्वविद्यालय बनाया जा सकता है? मेरा दुसरा प्रश्न ...(व्यवधान)...

श्री सभापतिः दूसरा मत पूछिए।

डा. अबरार अहमरः यू.जी.सी. की रिकमेंडेशन्स और प्लानिंग कमीशन की रिकमेंडेशन्स के संबंध में उड़ीसा से संबंधित प्रश्न के उत्तर में जो कहा है, अगर वही बात राजस्थान पर भी लागू होती है तो माननीय मंत्री जी, मैं यह अच्छी तरह से जानता हूं कि सरकार जब किसी विश्वविद्यालय को केन्द्रीय विश्वविद्यालय बनाना चाहती है तो सिफारिश उसके अनुरूप आ सकती हैं।

डा. मुरली मनोहर जोशी: सभापति जी, हमारी सरकार सिफारिशों को मेन्युपुलेट नहीं करती। हम तो जो विशेषज्ञ और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के लोग कहते हैं उसके अनुसार जाते हैं। समितियां बनी हुई हैं जो विश्वविद्यालयों का एक्रिडिटेशन कर रही हैं कि वे किस स्तर के हैं। इसके बाद विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सिफारिश करेगा कि उन विश्वविद्यालय अनुदान आयोग सिफारिश करेगा कि उन विश्वविद्यालयों ....(व्यवधान)...

डा. अबरार अहमद: मानदंड क्या हैं?

श्री सभापतिः मानदंड दिए हुए हैं।

डा. मुरली मनोहरः उन विश्वविद्यालयों का स्तरीकरण कहां हो, उनका उन्नयन कहां हो। वे जिनको छांटेंगे, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विकसित करने के लिए, उन्हें सहायता दी जाएगी। मानदंडों का इसमें कोई प्रश्न नहीं है।

DR. M.N. DAS: I am anguished ...*{Interruptions)*...the Education Minister referred to the Central Universities ....*(Interruptions)*

श्री सभापतिः देखिए, आप बीच में मत कहिए, मैं आपको हमेशा चांस देता हूं ...(**व्यवधान**)... आज नहीं मिला ...(**व्यवधान**)... दूसरे लोगों को मिल रहा है, मैंने तो नहीं लिया है ...(**व्यवधान**)... बैठिए ...(**व्यवधान**)... बैठिए ...(**व्यवधान**)...

राज्यों में कृषि विज्ञान केन्द्र

*447. **श्री जानर्दन पुजारी**: †
श्री के. रहमान खान:
क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

†सभा में यह प्रश्न श्री जनार्दन पुजारी द्वारा पूछा गया।